

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार की "भ्रष्टाचार को कतई न बर्दाश्त करने" की नीति भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगी।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और सहयोगी दल की तरफ से अनुच्छेद 370 और 35 ए को बहाल करने बारे लाए गए प्रस्ताव की आलोचना की।
- कैदियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से करनाल की जिला जेल में श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान दिया गया।
- जेल मंत्री अरविन्द शर्मा ने कहा कि जेलों में सुधार के लिए और कदम उठाए जाएंगे।
- वन रैंक वन पेंशन योजना ने 10 साल पूरे किए, हरियाणा के पूर्व सैनिकों ने इसे सरकार की परिवर्तनकारी योजना बताया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार की "भ्रष्टाचार को कतई न बर्दाश्त करने" की नीति भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगी। श्रीमती मुर्मु आज नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई पहल की हैं। इनमें से कुछ पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, ई मार्केटप्लेस और आर्थिक अपराधी अधिनियम का उदाहरण दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में देरी या कमजोर कार्रवाई अनैतिक व्यक्तियों को बढ़ावा देती है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और सहयोगी दल की तरफ से अनुच्छेद 370 और 35 ए को बहाल करने बारे लाए गए प्रस्तावकी आलोचना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 को पीड़ियों ने भुगता है। बड़े नेताओं ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35 ए खत्म कर जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ा। जिसके बाद वहाँ शांति बहाल की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दलों से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं देखा जा रहा है। वो घाटी के बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा कि क्या वह देश विरोधी ताकतों के साथ है -

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता हर हाल में देश की एकता तथा अखंडता के लिए दृढ़ता से खड़ी रहेगी। देश के लोग इससे खिलवाड़ करने वालों को करारा जवाब देंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के 92 विकास कार्यों के लिए 18 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन विकास कार्यों में सड़क व पुलिया निर्माण, आरसीसी पाईप डालना, पीवीसी पाइप, आई.पी.ब्लॉक, शेड निर्माण और दिवार का निर्माण इत्यादि प्रमुख कार्य शामिल हैं।

कैदियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से आज करनाल की जिला जेल में भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और जेल एवं पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने शिरकत की। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि आज जेल में बंद कैदियों को गीता का संदेश दिया गया ताकि कैदी जान सकें कि कैसे वे निराशा से दूर रह सकते हैं और अपनी सोच में परिवर्तन ला कर अपना भविष्य सुधार सकते हैं।

एक प्रश्न के उत्तर में गीता मनीषी ने कहा कि करनाल जेल में गौशाला बनकर पूरी तरह तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। गौशाला में जेल बंदी ही सेवा करेंगे और उनके दूध का इस्तेमाल भी यही किया जाएगा जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की यह इच्छा थी कि यह कार्यक्रम जेलों से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि जेलों में बंद लोग थोड़े से गुस्से के कारण मन का नियंत्रण खो बैठे जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। गीता का ज्ञान लेकर मन और भावों को काबू में कर ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जेलों में सुधार के लिए और कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि जो संकल्प पत्र हमारी सरकार ने बनाया है उसे जल्द पूरा करें।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के भूखंड आवंटियों को एन्हांसमेंट से संबंधित मामलों के निपटान के लिए विवादों का समाधान योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 127वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह घोषणा की। बैठक में कुल 65 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना की शुरुआत गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को होगी जो 6 माह तक लागू रहेगी। इससे लगभग 7000 से अधिक भूखंड आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी।

वन रैंक वन पेंशन योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लंबे समय से चली आ रही सैनिकों की मांग को पूरा करते हुए वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया था। यह अपने सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हरियाणा के पूर्व सैनिकों ने कहा है कि पूर्व सैनिकों के लिए उचित और समान पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की परिवर्तनकारी योजना है।

वायु सेना से सेवामुक्त हुए सार्जेंट पवन शर्मा ने कहा -

इस योजना में समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को समान पेंशन मिलती है, चाहे इनके सेवानिवृत्ति की तारीख कोई भी हो।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वच्छता के विशेष अभियान का चौथा संस्करण पूरा कर लिया है। यह अभियान देशभर में 600 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों में चलाया गया है। इसका उद्देश्य संस्थागत सफाई, लम्बित मामलों का निपटान, सौंदर्यीकरण और जगह का अधिकतम इस्तेमाल था। मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान 78 हजार, 543 किलोग्राम कचरे का निपटान किया गया और इसे बेचकर 85 लाख, 99 हजार, 249 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

एक महीने तक चले इस अभियान में 391 जन शिकायतों और 72 अपीलों का निपटान किया गया। इसके अलावा 65 हजार वर्ग फुट का कार्यालय स्थान भी खाली किया गया।